भारतीय खाद्य निगम सी ठेकेदारी प्रथा का उन्मूलन किया जाना

4173. **श्री रामगोपाल यादव जी:** क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारतीय खाद्य निगम से ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या सरकार इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा पारित प्रस्ताव को पहले ही अपनी मान्यता प्रदान कर चुकी है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव पर सरकार कब तक और क्या निर्णय लेगी तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव): (क) जी, नहीं। भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में अनियमित और मौसमी स्वरूप के कार्य को देखते हुए एक साथ ठेका प्रणाली समाप्त करना वांछनीय नहीं समझा गया है।

(ख) और (ग) चूंकि अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में इस विषय संबंधी अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज अपनाने के बारे में मतैक्य नहीं था इसलिए भारत सरकार द्वारा इस संबंध में कोई निर्णय लेने का प्रश्न नहीं उठता।

Hike in Levy Sugar Price

4174. SHRIMATI JAYAPRADA NAHATA: Will the Minister of FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government propsoe to hike levy sugar price;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the steps envisaged for supply of levy sugar for public distribution system regularly?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI SATYA PAL SINGH YADAV): (a) and (b) The matter is under examination in the Government.

(c) With the decision to purchase upto 12 lakh tonnes of sugar from the free sale quota of domestic mills to meet the deficit in the levy account, necessary arrangements have been made to ensure adequate and regular supply of sugar under the Public Distribution System in the 1997-98 sugar season.

राज्यों के खाद्य मंत्रियों की बैठक में चर्चित विषय

4175. **श्री ईश दत्त यादव:**
श्री राम गोपाल यादव:

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जून, 1998 के अंतिम सप्ताह में राज्यों के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रियों की कोई बैठक दिल्ली में बुलायी थी;

(ख) यदि हां, तो उस बैठक में किन-किन मुख्य विषयों पर चर्चा की गई; और

(ग) बैठक में चर्चित विषयों पर सरकार ने क्या-क्या निर्णय लिए?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव): (क) से (ग) चीनी उद्योग संबंधी महाजन समिति की रिपोर्ट में शामिल विभिन्न सिफारिशों पर राज्य सरकारों के विचार जानने के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति और चीनी उद्योगों विभाग के प्रभारी राज्य मंत्रियों की बैठक 25.6.98 को आयोजित की गई थी। इस बैठक में 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। बैठक के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चलाने संबंधी विधियों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र को चीनी का आवंटन करने के मानदंड, वितरण नियंत्रण को जारी रखने की आवश्यकता, त्यौहारों के लिए चीनी का अधिक आवंटन करने की आवश्यकता, मिलों के पास रखे चीनी के अत्यधिक स्टॉक के कारण पेश आई समस्याएं, किसानों को गन्ना मूल्य के बकायों के भुगतान के कारण पेश होने वाली समस्याएं, डीलर लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाना और चीनी रिलीज आदेश को समय से जारी करने की आवश्यकता आदि संबंधी मामलों पर विभिन्न विचार व्यक्त किए गए थे। किसी भी मामले पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया था।